सरस्वती

बनाम

बाबू

(आपराधिक अपील संख्या 1999/2013)

25 नवम्बर 2013

(न्यायमूर्ति सुधांसु ज्योति मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति बनाम गोपाल गौड़)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 - एस.एस. 2(जी) 3, 18, 19, 20 और 22 - याचिका - अदालत का आदेश जिसमें पति को पत्नी को साझा घर में रहने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है - पति द्वारा आदेश की अवहेलना - क्या पति का कृत्य अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा है- माना गया। पति का कृत्य पूरी तरह से धारा 3 के दायरे में आता है- पति द्वारा पत्नी के खिलाफ लगातार घरेलू हिंसा को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि अधिनियम लागू होने से पहले के पक्षों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता - प्रताड़ित होने पर पत्नी भरण-पोषण के साथ-साथ सुरक्षा आदेश और निवास आदेश की भी हकदार है। इसके अलावा, वह पति द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्यों के परिणामस्वरूप उसे हुई क्षति जिसमें मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक परेशानी सम्मिलित है, के लिये मुआवजे और क्षतिपूर्ति की भी हकदार है। पति को पांच लाख रूपये की सीमा तक मुआवजा व क्षति का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

शब्द और वाक्यांश - 'घरेलू हिंसा' - का अर्थ, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के संदर्भ में।

प्रत्यर्थी की अपीलकर्ता-पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 और 22 के तहत राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की। अदालत ने प्रत्यर्थी को उसे भरण-पोषण देने का निर्देश दिया और पुलिस को यह निर्देश करते हुए कि वह निवास आदेश को लागू करने में पत्नी को सुरक्षा दें, उसके वैवाहिक घर में रहने हेतु निवास का आदेश भी दिया। प्रत्यर्थी-पति ने न्यायालय के आदेश के बावजूद अपीलकर्ता को साझा निवास गृह में रहने की अनुमति नहीं दी। अपीलकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी ने गलत पता दिया और उच्च न्यायालय को गुमराह किया।

उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश द्वारा माना कि यद्यपि पति के अपमानजनक कृत्यों को अन्य अधिनियमों के तहत अपराध के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसे अधिनियम लागू होने के पूर्व 2005 के अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के कृत्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जी) में कहा गया है कि "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा है। धारा 3 का खंड (iv) "आर्थिक दुरुपयोग" से संबंधित है जिसमें संसाधनों या सुविधाओं तक निरंतर पहुंच जिसमें साझा घर तक पहुंच भी शामिल है जिनका उपयोग करने की पीडित महिला घरेलू संबंध के कारण हकदार है, पर प्रतिषेध और प्रतिबंध शामिल है, जो कि पीड़ित व्यक्ति घरेलू संबंधों के

आधार पर उपयोग करने या आनंद लेने का हकदार है। जैसा कि स्पष्ट है धारा 3(iv) का खंड (सी)। [पैरा 12] [927-सी-डी]

2. वर्तमान मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बाद भी प्रत्यर्थी-पति ने अपीलकर्ता-पत्नी को साझा घरेलू वैवाहिक घर में रहने की अनुमति नहीं दी, प्रत्यर्थी-पति द्वारा अपीलकर्ता-पत्नी के विरुद्ध घरेलू हिंसा की निरंतरता बनी हुई है। ऐसी लगातार जारी घरेलू हिंसा को देखते हुए, निचली अदालतों के लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के लागू होने से पहले की गई है और क्या ऐसा कृत्य अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित 'घरेलू हिंसा' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। [पैरा 13] [927-ई-एफ]

3. प्रत्यर्थी-पति का कृत्य स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 3 के दायरे में आता है जो "घरेलू हिंसा" को व्यापक रूप से परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि आदेश पारित करते समय अधिनियम के लागू होने से पहले पक्षों के आचरण को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। यह एक ऐसा मामला है जहां प्रत्यर्थी-पति ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का पालन नहीं किया है। उन्होंने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष गलत बयान देकर अदालत को भी गुमराह किया। 2000 से प्रताड़ित की जा रही अपीलकर्ता-पत्नी अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत संरक्षण आदेश और निवास आदेश के साथ-साथ भरण-पोषण की भी हकदार है, जैसा कि अधिनियम की धारा 20 (डी) के तहत विचारण न्यायालय ने अनुमति दी है। इन राहतों के

अलावा, वह प्रत्यर्थी-पति द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई मानसिक यातना और भावनात्मक परेशानी सहित चोटों के लिए मुआवजे और क्षति की भी हकदार है। इसलिए, नीचे की अदालतों द्वारा दी गई राहत के अलावा, अपीलकर्ता-पत्नी को प्रत्यर्थी-पति द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में 5,00,000/- रुपये की सीमा तक मुआवजा और क्षति का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 15] [928-सी-जी]

वी.डी. भनोट बनाम सविता भनोट (2012) 3 एससीसी 183: 2012 (1) एससीआर 867 - पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ:

2012 (1) एससीआर 867	पर भरोसा किया	पैरा 14

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1999/2013

मद्रास उच्च न्यायालय के सीआरएल आर.सी.की संख्या 1321/2010 में निर्णय और आदेश के दिनांक 13.12.2011 के से।

अपीलकर्ता के लिए आर. बालासुब्रमण्यम, टी. हरीश कुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से एस.डी. द्वारका नाथ, डॉ. कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई। यह अपील अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13 दिसंबर, 2011 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने

अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण मामले को खारिज कर दिया और इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

वर्तमान विवाद के पक्षकारों ने एक-दूसरे से विवाह किया है और उक्त विवाह 17 फरवरी, 2000 को संपन्न हुआ था। अपीलकर्ता के अनुसार, वह स्त्रीधन के रूप में 50 सोने के आभूषण और 1 किलो चांदी के सामान लाई थी, साथ ही 10,000/- रुपये भी दिए गए थे। प्रत्यर्थी. शादी के बाद अपीलकर्ता पाडी, चेन्नई में अपने वैवाहिक घर में रहती थी। शादी के चार महीने बाद, प्रत्यर्थी-पति और उसके परिवार ने नकदी और गहनों के रूप में अधिक दहेज की मांग की। अपीलकर्ता उक्त मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी और उसके ससुराल वालों ने उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया। अपीलकर्ता का एक और आरोप यह है कि अपीलकर्ता को उसके वैवाहिक घर से बाहर भेजने के बाद, प्रत्यर्थी-पति ने फिर से शादी करने का इरादा किया। ऐसी अफवाह सुनने पर, अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद "एचएम अधिनियम, 1955" के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत याचिका दायर की। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के समक्ष 2001 का एचएमओपी नंबर 216।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-पति ने दोनों के बीच विवाह विच्छेद के लिए प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के समक्ष एचएमए अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (आईए) और (iv) के तहत 2002 का एचएमओपी नंबर 123 दायर किया।

अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी 5 अप्रैल, 2006 को, विद्वान प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु ने प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर विवाह विच्छेद की याचिका को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी के वैवाहिक घर को छोड़कर अलग निवास स्थापित करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

वर्ष 2008 में अपीलकर्ता ने सी.आर.एल. दायर किया। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (इसके बाद इसे "पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 के रूप में संदर्भित) की धारा 19, 20 और 22 के तहत राहत की मांग करने वाले प्रत्यर्थी के खिलाफ विद्वान XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई के समक्ष 2008 का एमपी नंबर 2421 ")। विद्वान XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई ने आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी और प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता को उसके चिकित्सा व्यय, भोजन, आश्रय और कपड़ों के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति माह 2,000/- रुपये का रखरखाव देने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता का प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध है और प्रत्यर्थी की पत्नी होने के नाते अपीलकर्ता को साझा घर में रहने का अधिकार है। निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निवास आदेशों के कार्यान्वयन के लिए अपीलकर्ता को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया था और सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

प्रत्यर्थी-पति ने व्यथित होकर चेन्नई में सत्र न्यायालय (पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश) के समक्ष 2008 की आपराधिक अपील संख्या 339 दायर की।

इस बीच, XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलकर्ता-पत्नी संरक्षण अधिकारी के साथ प्रत्यर्थी-पति के साथ रहने के लिए अपने वैवाहिक घर चली गई। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया और अपीलकर्ता-पत्नी को घर में प्रवेश करने से मना कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चला गया।

22 दिसंबर, 2008 को, अपीलकर्ता ने विद्वान XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई के आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और इसे धारा 31 के तहत 2008 की एफआईआर संख्या 947 के रूप में अंबातुर टी 3 कोराट्टूर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 के 32 और 74। यह मामला विद्वान XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई को सौंपा गया था और 2011 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 636 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

इस बीच, प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर 2008 की आपराधिक अपील संख्या 339 को 21 अक्टूबर, 2010 को चेन्नई में सत्र न्यायालय (पांचवें अतिरिक्त न्यायाधीश) द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। सत्र न्यायालय ने उक्त आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। प्रत्यर्थी-पति ने अपीलकर्ता-पत्नी को साझा घर में रहने की अनुमति नहीं देकर उसके खिलाफ घरेलू हिंसा के कृत्यों को करने से रोक दिया

और प्रत्यर्थी को प्रत्यर्थी की मां के स्वामित्व वाले घर में रहने का निर्देश दिया और प्रत्यर्थी-पति द्वारा अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में 2,000/- प्रति माह का भरण-पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा।

3. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता-पत्नी ने सी.आर.एल. दायर किया। उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की आरसी संख्या 1321। उक्त पुनरीक्षण आवेदन में 2010 की एक आपराधिक विविध याचिका संख्या 1 भी दायर की गई थी। 23 दिसंबर, 2010 को, उच्च न्यायालय ने चेन्नई में विद्वान सत्र न्यायालय (पांचवें अतिरिक्त न्यायाधीश) द्वारा पारित उपरोक्त आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

4. इस बीच, जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, विद्वान XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई ने 24 फरवरी, 2011 को सीआरएल में एक आदेश पारित किया। विविध. याचिका संख्या 636/2011 (एफआईआर संख्या 947/2008 से उत्पन्न) और एसएचओ, अंबातुर टी3 कोराट्टूर पुलिस स्टेशन को राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में प्रत्यर्थी के घर का दरवाजा तोड़ने और अपीलकर्ता के लिए आवास बनाने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में प्रत्यर्थी के घर में सामान के बारे में पूछताछ करने के लिए एसएचओ को निर्देश दिया गया और साथ ही प्रत्यर्थी के साथ-साथ संरक्षण अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी-पति ने 23 दिसंबर, 2010 के रोक के आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की और 9 मार्च, 2011 के आदेश के जरिए उच्च न्यायालय ने रोक के आदेश को रद्द कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि अपीलकर्ता-पत्नी अपने पति के साथ जा सकती है और रह सकती है। गुडुवनचेरी में अपने

किराये के आवास में। जैसा कि उपरोक्त आदेश का प्रत्यर्थी-पति द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, अपीलकर्ता-पत्नी ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 मार्च, 2011 के आदेश की अवज्ञा करने के लिए प्रत्यर्थी-पति के खिलाफ 2011 की अवमानना याचिका संख्या 958 दायर की।

5. उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई, 2011 के आदेश के तहत निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अवमानना याचिका बंद कर दी:

> "एलडी द्वारा की गई स्पष्ट प्रस्तुति के मद्देनजर। प्रत्यर्थी के वकील के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा इस अदालत के समक्ष उपस्थित होकर दिए गए बयान में कहा गया है कि प्रत्यर्थी अवमानना याचिकाकर्ता को दरवाजा नंबर 80, कर्पागम्बल नगर, नादिवरम, गुडुवनचेरी, चेन्नई में परिसर के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोकने का वचन देता है। और अवमानना याचिकाकर्ता भी 01.08.2011 से उपरोक्त परिसर पर कब्जा करने और रहने के लिए सहमत हो गया, अवमानना याचिका बंद कर दी गई है।"

6. इसके बाद अपीलकर्ता ने पुलिस उप निरीक्षक, गुडुवनचेरी के समक्ष अभ्यावेदन दिया और कहा कि प्रत्यर्थी-पति ने गलत पता दिया है और अदालत के आदेश का पालन करने के लिए, अपीलकर्ता उस पते पर गया और पूछताछ करने पर पता चला कि पता फर्जी था. अपीलकर्ता ने एक शिकायत प्रस्तुत की और पुलिस से वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रत्यर्थी से पूछताछ करने का अनुरोध किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत के आदेश को उसके अक्षरशः लागू किया गया है।

7. जब मामला पुलिस के समक्ष लंबित था, तो उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक विविध मामले का फैसला किया और माना कि यद्यपि प्रत्यर्थी के अपमानजनक कृत्यों को अन्य अधिनियमों के तहत अपराध के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसे घरेलू कृत्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है। अधिनियम लागू होने तक पीडब्लयूडी अधिनियम, 2005 के तहत हिंसा। हाई कोर्ट ने पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया।

8. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया है:

> "4. विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न यह उठता है कि क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले किए गए कार्यों को जो अधिनियम में दी गई जानकारी के अनुसार 'घरेलू हिंसा' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, आधार बन सकते हैं। एक कार्रवाई का।"

9. उच्च न्यायालय ने पक्षों द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करने के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:

> "5. यह अदालत सबसे पहले इस बात पर विचार करेगी कि क्या ऐसे कार्य जो अब घरेलू हिंसा का गठन करते हैं लेकिन अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए थे, वे इसके तहत कार्रवाई का आधार बनेंगे। ऊपर उद्धृत प्राधिकारियों के प्रति उचित सम्मान के साथ, यह अदालत सूचित करेगी कि मूलभूत मुद्दे का समाधान नहीं किया गया

है। यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई गलत कार्य जो क्रूरता और दहेज की मांग जैसे अपराध हो सकते हैं, उन्हें अधिनियम के लागू होने तक "घरेलू हिंसा" का विवरण नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अपमानजनक कृत्यों को अन्य अधिनियमों के तहत अपराध के रूप में माना जा सकता था, लेकिन अधिनियम के लागू होने तक इसे 'घरेलू हिंसा' के कृत्य के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसलिए, अधिनियम के लागू होने तक जो अधिनियम में परिभाषित 'घरेलू हिंसा' नहीं थी, वह किसी कार्रवाई का आधार नहीं बन सकती थी। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, लेकिन अधिनियम के लागू होने से पहले किसी भी तारीख पर इस कहावत को लागू करने से अधिनियम के लागू होने से पहले मौजूद अपराध के ज्ञान का ही आरोप लगाया जा सकता है। यह सच है कि यह केवल अधिनियम के तहत पारित आदेशों का उल्लंघन है जिसे दंडनीय बनाया गया है। लेकिन वे आदेश केवल घरेलू हिंसा के कृत्यों के मामले में ही पारित किए जा सकते थे। अधिनियम के पारित होने तक यह ज्ञात नहीं था कि घरेलू हिंसा क्या है और यह 'घरेलू हिंसा' की शिकायत का आधार नहीं बन सकती थी।"

10. ट्रायल कोर्ट (XIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई दिनांक 5 दिसंबर, 2008) द्वारा पारित फैसले से हम पाते हैं कि

अपीलकर्ता ने अपने पति बाबू के खिलाफ पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत धारा 18, 19, 20 और 22 के तहत राहत की की मांग क ग करते हुए याचिका दायर की की। 2005 की धारा 18, 19, 20 अौर 22 इस प्रकार पढ़ें:

"18. सुरक्षा आदेश - मजिस्ट्रेट, पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है। और प्रत्यर्थी को प्रतिबंधित करें-

(ए) घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करना;

(बी) घरेलू हिंसा के कृत्यों को करने में सहायता करना या उकसाना;

(सी) पीड़ित व्यक्ति के रोजगार के स्थान में प्रवेश करना या, यदि पीड़ित व्यक्ति एक बच्चा है, उसके स्कूल या किसी अन्य स्थान पर जहां पीड़ित व्यक्ति अक्सर जाता है;

(डी) व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक संपर्क सहित, पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में संवाद करने का प्रयास करना;

(ई) पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रत्यर्थी द्वारा एकल रूप से उपयोग की गई या धारित या दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली या धारित या उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति, ऑपरेटिंग बैंक लॉकर या बैंक खातों को अलग करना, जिसमें उसका

स्त्रीधन या दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई कोई अन्य संपत्ति शामिल है। या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उनके द्वारा अलग से;

(च) आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति पर हिंसा करना जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से सहायता देता है;

(छ) सुरक्षा आदेश में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।

19 निवास आदेश-(1) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, निवास आदेश पारित कर सकता है -

क) प्रत्यर्थी को साझा घर से पीड़ित व्यक्ति को बेदखल करने या किसी अन्य तरीके से उसके कब्जे में गड़बड़ी करने से रोकना, चाहे प्रत्यर्थी का साझा घर में कानूनी या न्यायसंगत हित हो या नहीं;

बी) प्रत्यर्थी को साझा घर से खुद को दूर करने का निर्देश देना;

ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी रिश्तेदार को साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है;

घ) प्रत्यर्थी को साझा घर को अलग करने या उसका निपटान करने या उस पर कब्ज़ा करने से रोकना;

ई) प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के अलावा साझा घर में अपने अधिकारों का त्याग करने से रोकना; या

च) प्रत्यर्थी को पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर के वैकल्पिक आवास को सुरक्षित करने का निर्देश देना जैसा कि उसे साझा घर में मिलता था या यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो उसके लिए किराए का भुगतान करना:

बशर्ते कि खंड (बी) के तहत कोई भी आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पारित नहीं किया जाएगा जो महिला है।

(2) मजिस्ट्रेट कोई अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है या कोई अन्य निर्देश पारित कर सकता है जिसे वह पीड़ित व्यक्ति या ऐसे पीड़ित व्यक्ति के किसी बच्चे की सुरक्षा के लिए उचित रूप से आवश्यक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा को रोकने के लिए प्रत्यर्थी से ज़मानत के साथ या उसके बिना एक बांड निष्पादित करने की मांग कर सकता है।

(4) उप-धारा (3) के तहत एक आदेश को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के तहत एक आदेश माना जाएगा और तदनुसार निपटाया जाएगा।

(5) उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत आदेश पारित करते समय, अदालत निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सुरक्षा देने का निर्देश भी दे सकती है। आदेश के कार्यान्वयन में पीड़ित व्यक्ति या उसकी या

उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करना।

(6) उप-धारा (1) के तहत आदेश देते समय, मजिस्ट्रेट पार्टियों की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, किराया और अन्य भुगतानों के निर्वहन से संबंधित प्रत्यर्थी दायित्वों पर लगा सकता है।

(7) मजिस्ट्रेट उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए संपर्क किया गया है।

(8) मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति को उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा वापस लौटा दे, जिसकी वह हकदार है।

20. मौद्रिक राहतें-(1) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय , मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को पीड़ित व्यक्ति और किसी भी बच्चे द्वारा किए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत देने का निर्देश दे सकता है। घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की राहत में शामिल हो सकता है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है,

(ए) कमाई का नुकसान;

(बी) चिकित्सा व्यय;

(सी) पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति के विनाश, क्षति या हटाने के कारण होने वाली हानि; और

(डी) पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ उसके बच्चों के लिए भरण-पोषण, यदि कोई हो, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य कानून की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के आदेश के तहत या इसके अतिरिक्त आदेश शामिल है। फिलहाल लागू है.

(2) इस धारा के तहत दी गई मौद्रिक राहत पर्याप्त, निष्पक्ष और उचित होगी और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुरूप होगी।

(3) मजिस्ट्रेट के पास मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार उचित एकमुश्त भुगतान या भरण-पोषण के मासिक भुगतान का आदेश देने की शक्ति होगी।

(4) मजिस्ट्रेट उप-धारा (1) के तहत दिए गए मौद्रिक राहत के आदेश की एक प्रति आवेदन के पक्षकारों और उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भेजेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर प्रत्यर्थी रहता है।

(5) प्रत्यर्थी उप-धारा (1) के तहत आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पीड़ित व्यक्ति को दी गई मौद्रिक राहत का भुगतान करेगा।

(6) उप-धारा (1) के तहत आदेश के संदर्भ में भुगतान करने में प्रत्यर्थी की ओर से विफलता पर, मजिस्ट्रेट नियोक्ता या प्रत्यर्थी के देनदार को सीधे पीड़ित व्यक्ति को

भुगतान करने का निर्देश दे सकता है या प्रत्यर्थी के कारण या अर्जित वेतन या वेतन या ऋण का एक हिस्सा अदालत में जमा करें, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा देय मौद्रिक राहत के लिए समायोजित किया जा सकता है।

22. मुआवजा आदेश.-इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली अन्य राहतों के अलावा, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर एक आदेश पारित कर सकता है, जिसमें प्रत्यर्थी को मानसिक यातना सहित चोटों के लिए मुआवजा और क्षति का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। और भावनात्मक संकट, जो उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुआ।"

11. ट्रायल कोर्ट ने पीडब्ल्यू अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता-पत्नी को अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बाद भी प्रत्यर्थी-पति द्वारा वैवाहिक घर में प्रवेश करने से रोका गया था, धारा 18 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई। धारा 19 के तहत प्रत्यर्थी-पति को अपीलकर्ता-पत्नी को साझा घर में प्रवेश करने की अनुमति देने और अपीलकर्ता-पत्नी के कब्जे को परेशान न करने और उसके चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति माह 2,000/- रुपये का रखरखाव देने का निर्देश दिया गया। भोजन और अन्य खर्च। हालाँकि, अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में कोई मुआवजा या हर्जाना नहीं दिया गया।

प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तामीली के बावजूद, प्रत्यर्थी द्वारा याचिका में दिए गए कथनों से इनकार करते हुए कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

12. पीडब्ल्युडी अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जी) में कहा गया है कि "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो अधिनियम, 2005 की धारा 3 में दिया गया है। धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा है। धारा 3 का खंड (iv) "आर्थिक दुरुपयोग" से संबंधित है जिसमें संसाधनों या सुविधाओं तक निरंतर पहुंच पर प्रतिबंध या प्रतिबंध शामिल है, जो कि पीड़ित व्यक्ति घरेलू संबंधों के आधार पर उपयोग करने या आनंद लेने का हकदार है, जिसमें साझा घर तक पहुंच भी शामिल है, जैसा कि स्पष्ट है धारा 3(iv) का खंड (सी)।

13. वर्तमान मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बाद भी प्रत्यर्थी-पति ने अपीलकर्ता-पत्नी को साझा घरेलू वैवाहिक घर में रहने की अनुमति नहीं दी है, हम मानते हैं कि निरंतरता बनी हुई है प्रत्यर्थी-पति द्वारा अपीलकर्ता-पत्नी के विरुद्ध की गई घरेलू हिंसा। इस तरह की जारी घरेलू हिंसा को देखते हुए, निचली अदालतों के लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले की गई है और क्या ऐसा कार्य परिभाषा के अंतर्गत आता है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत परिभाषित 'घरेलू हिंसा' शब्द की।

14. दूसरा मुद्दा यह है कि क्या धारा 18, 19 और 20 के तहत आदेश पारित करते समय पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 के शुरू होने से

पहले भी पार्टियों के आचरण पर विचार किया जा सकता था, वीडी भनोट बनाम में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। सविता भनोट (2012) 3 एससीसी 183। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

> "12. हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक शिकायत को देखते समय, पीडब्ल्यूडी अधिनियम के लागू होने से पहले भी पार्टियों के आचरण को पारित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। इसकी धारा 18, 19 और 20 के तहत एक आदेश। हमारे विचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सही माना है कि भले ही एक पत्नी, जो अतीत में एक घर साझा करती थी, लेकिन अधिनियम लागू होने पर अब ऐसा नहीं कर रही थी, फिर भी वह पीडब्ल्यूडी की सुरक्षा की हकदार होगी। अधिनियम, 2005,"

15. हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी-पति का कृत्य पूरी तरह से पीडब्ल्युडी अधिनियम, 2005 की धारा 3 के दायरे में आता है, जो व्यापक रूप से "घरेलू हिंसा" को परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले पार्टियों के आचरण को आदेश पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। यह एक ऐसा मामला है जहां प्रत्यर्थी-पति ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का पालन नहीं किया है। उन्होंने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष गलत बयान देकर अदालत को भी

गुमराह किया। अपीलकर्ता-पत्नी को 2000 से प्रताड़ित किया जा रहा है, वह पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 की धारा 18 और 19 के तहत सुरक्षा आदेश और निवास आदेश के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 20 (डी) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमत भरण-पोषण की हकदार है। 2005 इन राहतों के अलावा, वह प्रत्यर्थी-पति द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई मानसिक यातना और भावनात्मक परेशानी सहित चोटों के लिए मुआवजे और क्षति की भी हकदार है। इसलिए, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दी गई राहतों के अलावा, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता-पत्नी को प्रत्यर्थी-पति द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में 5,00,000/- रुपये की सीमा तक मुआवजा और क्षति का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

16. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रत्यर्थी-पति को तीन महीने के भीतर निवास और रखरखाव के संबंध में निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों और निर्देशों का पालन करने के निर्देश के साथ रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थी-पति को इस आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में 5,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई अलग आदेश नहीं होगा।

के.के.टी. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री ममता मेनारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।